कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–मुंगेली (छ.ग.)

PH. NO. 07755-264140 email. Id. mungelideo@gmail.com

क्रमांक/5867/मान्यता अनुमति/ 2018-19 मुंगेली दिनांक 12/12/2018
//नवीनीकरण//संशोधन//

प्रति,

प्रबंधन वर्ग

मां दुर्गा शिक्षण समिति
लोरमी
जिला मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत् विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 20/09/2017 के संदर्भ में और एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त में मां भारती उच्च माध्यमिक शाला लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.) (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक के माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए जो 01/04/2018 से 31/03/2021 तक प्रभावशील रहेगा, अस्थायी मान्यता/अनुमति प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति, परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा 8वीं के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का कानून 2009 (एनेक्सर) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून (एनेक्सर 2) विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या का 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसें प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न बच्चे का यह उसके माता–पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण–पत्र के अभाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्मस्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चें को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि –
   (क) प्रवेशित किसी भी बच्चें को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला–जायेगा।
   (ख) किसी भी बच्चें को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
   (ग) किसी भी बच्चें को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
   (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ड) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।

(च) शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहिहत नियुक्त किये जातें है। 5 वर्ष समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ प्राप्त करेंगे।

(छ) शिक्षकों को देय वेतन एवं भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उपनियम (1) के तहत सरकार द्वारा यथा अनशंसित होगी।

(ज) शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्त्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेगें।

8. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।

9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपतिक छात्रों को प्रवेश देगी।

10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेगें।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

- कुल निर्माण का क्षेत्रफल
- खेल के मैदान का क्षेत्रफल
- अध्यापन कक्षाओं की संख्या
- प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भंडार हेतु कक्ष
- बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन
- बाधारहित पहुंच
- शिक्षण अधिगम् सामग्री/खेलकुद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धा

11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।

12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवसीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।

13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत् पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत् समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।

14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूल या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।

16. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नंबर 741 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी प्रत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए।

17. विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तो की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।

18. अन्य शर्ते एनेक्सर 3 के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला – मुंगेली छ.ग.

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक F -6-36/2018/20-तीन रायपुर, दिनांक

प्रेषक,

पी0के0 पांडेय
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रेषिति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE),
शिक्षा केन्द्र-2 कम्प्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषयः- सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबंद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत्- अशासकीय माँ भारती उ.मा. विद्यालय लोरमी, जिला मुंगेली, छ.ग. ।

=00=

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय माँ भारती उ.मा. विद्यालय लोरमी, जिला मुंगेली (छ0ग0) को शिक्षा सत्र 2018-19 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करता है ।

(पी0के0 पांडेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 29-9-18

पृ0 कमांक F-6-36/2018/20-तीन

प्रतिलिपिः-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर ।

02. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक अनुदान/CBSE/NOC/2018-19/411, दिनांक 17.07.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

.....02

0 कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ ।

04. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली, छत्तीसगढ़ ।

05. प्राचार्य, अशासकीय माँ भारती उ.मा. विद्यालय लोरमी, जिला मुंगेली, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

06. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ ।

28-9-18

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

स्कूल शिक्षा विभाग